रजिस्ट्री सं० डी० 222

REGISTERED NO. D-222

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 3] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 20, 1968 (पौष 30, 1889)

No. 3] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 20, 1968 (PAUSA 30, 1889)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

नोटिस
NOTICE

नीचे लिखे भारत के असाधारण राजपत्र 18 दिसम्बर 1967 तक प्रकाशित किये गये हैं :—

The undermentioned *Gazettes of India Extraordinary* were published up to the 18th December 1967 :—

अंक Issue No.	संख्या और तारीख No. and Date	द्वारा जारी किया गया Issued by	विषय Subjects
202	No. 196-ITC(PN/67, dated 18th December, 1967	Min. of Commerce	Import policy for Registered Exporters for the year April, 1967- March, 1968—nomination of manufacturers of mettallic yarn against export of Natural silk, Fabrics, Garments and made up articles.
203	No. 197-ITC(PM)/67 dated 21st December, 1967	Do.	Import Policy for Registered Exporters for the period April, 1967—March, 1968- Procedure for making nominations.
	No. 198-ITC (PN/67, dated 21st Dec., 1967	Do.	Import Policy for Registered Exporters for the year April 1967—March, 1968.
204	No. 199-ITC(PN)/67 dated 21st Dec., 1967	Do.	Surcharge on freight due to closure of Suez Canal and diversion of ships *via* Cape of Good Hope—Payment arrangements therefore against licences under W. 5 Aid and other Loans.
205	No. 4(46)-TEX(C)/67, dated 23rd Dec., 1967	Do.	Extending the date of term of Office of the All India Handloom Board.
206	No. F4(43)-BC/67, dated 23rd Dec., 1967	Min. of Finance	Establishment of National Credit Council.
207	No. 37/1/III/67/T, dated 27th Dec., 1967	Lok Sabha Secretariat.	Proroguing the Lok Sabha.
	संख्या 37/1/III/टी०, दिनांक 27 दिसंबर 1967	लोक सभा सचिवालय	लोक सभा का सत्रावसना करना ।
208	No. 13(38)/66/IOC, dated 27th Dec., 1967	Min. of Petroleum and Chemicals.	Accepting the recommendations made by the Retail Outlet Committee.
	संख्या 13 (38)/66/आई० ओ० सी० दिनांक 27 दिसंबर, 1967	पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय	फुटकर पंप समिति की सिफारिशें मंजूर करना ।
209	No. 200-ITC(PN)/67 dated 28th Dec., 1967	Min. of Commerce	Import Policy for Rubber Contraceptives (S. No. 41(i)(b)/(V) for the period April, 1967—March, 1968.
	No. 201—ITC(PN)/67 dated 28th Dec., 1967.	Do.	Import Policy for Registered Exporters for the year April, 1967—March 1968.
	No. 202—ITC(PN)/67 dated 28th Dec., 1967	Do.	Import Policy for Registered Exporters for the year April, 1967—March, 1968.

अंक Issue No.	संख्या और तरीख No. and Date	द्वारा जारी किया गया Issued by	विषय Subjects
	No. 203—ITC(PN)/67 dated 28th Dec., 1967	Min. of Commerce	Import Policy for Registered Exporters for the year April, 1967—March, 1968.
	No. 204—ITC(PN)/67, dated 28th Dec., 1967	Do.	Import Policy for Registered Exporters for the year April, 1967—March, 1968
	No. 205—ITC(PN)/67 dated 28th Dec., 1967.	Do.	Import Policy for Registered Exporters for the year April, 1967—March, 1968.
	No. 206—ITC(PN)/67, dated 28th Dec., 1967	Do	Import Policy for Registered Exporters for the year April, 1967—March, 1968.

A. V. BODAS, *Asstt. Manager (Tech.*

ऊपर लिखे असाधारण राजपत्रों की प्रतियां प्रकाशन प्रबन्धक, सिविल लाइन्स, दिल्ली के नाम मांगपत्र भेजने पर भेज दी जाएंगी। मांगपत्र प्रबन्धक के पास इन राजपत्रों के जारी होने की तारीख से दस दिन के भीतर पहुंच जाने चाहिएं ।

Copies of the *Gazette Extraordinary* mentioned above will be supplied on Indent to the Manager of Publications, Civil Lines, Delhi. Indents should be submitted so as to reach the Manager within ten days of the date of issue of these Gazettes.

विषय सूची (CONTENTS)

	पृष्ठ (Pages)
भाग I—खंड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	31
भाग I—खंड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	53
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . .	—
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . .	25
भाग II—खंड 1 अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	—
भाग II—खंड 2 विधेयक और विधेयकों सम्बन्धी प्रवर समितियों की रिपोर्ट .	—
भाग II—खंड 3—उप-खंड (1)—(रक्षा मन्त्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं) . . .	87
भाग II—खंड 3—उप-खंड (2)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं . . .	107
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश . . .	13
भाग III—खंड 1—महालेखापरीक्षक, संघ-लोक-सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के संलग्न तथा अधीन कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं .	31
भाग III—खंड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसचनाएं और नोटिसें .	17
भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं .	9
भाग III—खंड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिसें शामिल हैं .	15
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिसें . .	9
पूरक सं० 3—	
13 जनवरी 1968 को समाप्त होने वाले सप्ताह की महामारी सम्बन्धी साप्ताहिक रिपोर्ट .	73
6 जनवरी 1968 को समाप्त होने वाले सप्ताह के दौरान भारत में 30,000 तथा उससे अधिक आबादी के शहरों में जन्म, तथा बड़ी बीमारियों से हुई मृत्यु से सम्बन्धित आंकड़े .	85

	पृष्ठ Pages
PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations and Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	31
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave, etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	53
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Non-statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence	—
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave, etc. of Officers issued by the Ministry of Defence	25
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations	—
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills	—
PART II—SECTION 3.—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules, (including orders, bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)	87
PART II—SECTION 3.—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)	107
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence ..	13
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	31
PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Offices, Calcutta ..	17
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	9
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	15
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies	9
SUPPLEMENT No. 3—	
Weekly Epidemiological Reports for week-ending 13th January 1968	73
Births and Deaths from Principal diseases in towns with a population of 30,000 and over in India during week-ending 6th January 1968	85

भाग I—खण्ड 1

PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 8 जनवरी, 1968

सं० 2-प्रेज/68—राष्ट्रपति निम्नांकित व्यक्तियों को उनकी अति उत्कृष्ट वीरता के लिये अशोक चक्र प्रदान करने का अनुमोदन करते हैं :

1. श्री हुक्म सिंह,
   ग्राम गौर,
   छत्तरपुर, जिला,
   मध्य प्रदेश ।
2. श्री लखन सिंह,
   ग्राम गौर,
   छत्तरपुर जिला,
   मध्य प्रदेश ।
3. श्री गोविन्द सिंह,
   ग्राम गौर,
   छत्तरपुर जिला,
   मध्य प्रदेश ।
4. श्री तखत सिंह,
   ग्राम गौर,
   छत्तरपुर, जिला,
   मध्य प्रदेश । **(मरणोपरान्त)**

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—4 जनवरी 1966)

4 जनवरी, 1966 की रात को सशस्त्र डाकुओं ने मध्य प्रदेश के गौर ग्राम में ग्रामीणों को दूर रखने के लिए अन्धा-धुन्ध गोलियां चलाते हुये, श्री महाराज सिंह के मकान पर धावा बोल दिया। श्री गोबिन्द सिंह, पुत्र श्री महाराज सिंह तथा उनका भाई मकान से बाहर आने में सफल हो गये और सहायता के लिए चिल्लाये। कुछ ग्रामीण जिनमें सर्वश्री हुक्म सिंह, लखन सिंह तथा तख्त सिंह भी सम्मिलित थे, बचाव के लिये आये। डाकुओं ने उन पर गोली चलाकर एक ग्रामीण तथा श्री गोविन्द के भाई को जख्मी कर दिया। इसकी परवाह न कर, लाठी तथा बरछे लिये हुए ग्रामीणों ने हथियारों से अच्छी तरह लैस डाकुओं का मुकाबला किया। श्री गोविन्द सिंह मकान की दीवार पर चढ़ गये और वहां से 10 फुट नीचे आंगन में कूद गये जहां उनके पिता को रस्से से बांधकर

यातनायें दी जा रहीं थीं। वह श्री तख्त सिंह के साथ डाकुओं पर टूट पड़े जिन्होंने उनपर गोली चला दी। इस मुठभेड़ के दौरान सर्वश्री महाराज सिंह, तख्त सिंह तथा दो अन्य ग्रामीण मारे गये और श्री गोविन्द सिंह तथा उनका भाई बुरी तरह से जख्मी हो गये। इसके बावजूद, श्री हुक्म सिंह तथा श्री लखन सिंह लड़ते हुये मकान में पहुच गये और दो डाकुओं को घेर लिया। उनमें से एक तो कमरे की खपरैल की छत में सुराख कर बच निकलने में सफल हो गया किन्तु दूसरे डाकू को पकड़ने और कमरे में बन्द करने में वे सफल हो गये। उस समय तक दूसरे डाकुओं के छक्के छूट गये और वे भागने लगे। इसी बीच पुलिस घटना स्थल पर पहुंच गई और कमरे में बन्द डाकू को गिरफ्तार कर लिया और बाद में कुछ और भागे हुए डाकुओं को भी गिरफ्तार कर लिया गया।

सशस्त्र डाकुओं के विरुद्ध लड़ने में सर्व श्री हुक्म सिंह, लखन सिंह, गोविन्द सिंह तथा तख्त सिंह की शौर्यपूर्ण कार्रवाई वीरता और साहस का एक ज्वलन्त उदाहरण था।

5. श्री धनपत सिंह,
ग्राम खरेहटा,
जबलपुर जिला,
मध्य प्रदेश।

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—27 फरवरी 1967)

27 फरवरी, 1967 की रात को सशस्त्र डाकुओं ने मध्य प्रदेश में खरेहटा ग्राम में श्री दादूराम के मकान पर धावा बोल दिया। श्री दादू राम तथा उनकी पत्नी को निर्दयता से पीटा और यातनायें देकर उन्हें कीमती वस्तुओं का ठिकाना बताने के लिये बाध्य किया। कुछ समय बाद श्री दादूराम बेहोश हो गये और उनकी पत्नी ने मकान के उस स्थान की ओर इशारा किया जहां जेवर थे। इस बीच साथ के मकान के उनके पड़ोसी ने शोर सुना और खिड़की से झांकने की कोशिश की और अपनी टार्च से रोशनी की। डाकुओं ने उनपर गोली चला दी किन्तु वह बचने में सफल हो गये और गांव वालों को इसकी सूचना दी। श्री धनपत सिंह ने, जो पास ही रह रहे थे, बन्दूक की गोली की आवाज सुनी। उन्होंने फौरन अपनी लाठी उठा ली और तेजी के साथ बाहर निकलते हुये उन लोगों को पीछे आने को कहा जो उस समय तक वहां एकत्रित होने लग गये थे। डाकुओं ने अन्धा-धुन्ध गोलीबारी शुरु कर दी और कुछ ग्रामीण भाग गये। श्री धनपत सिंह ने ग्रामीणों को एकत्रित किया और मकान की ओर बढ़े। डाकू, जो श्री दादूराम की पत्नी का दूसरी सम्पत्ति का भी ठिकाना बताने के लिये गला दबा रहे थे, डर गये और 40,000 रुपये की सम्पत्ति लेकर भाग खड़े हुये। श्री धनपत सिंह ने अन्य लोगों के साथ डाकुओं का पीछा किया डाकुओं ने गोली चलाकर एक ग्रामीण को जख्मी कर दिया। इसकी परवाह न कर, श्री धनपत सिंह जो केवल एक लाठी लिये हुये थे, डाकुओं के मुखिया पर अपट पड़े जो 12 बोर की बन्दूक लिये हुये था। एक ग्रामीण की सहायता से वह डाकू से गुत्थम-गुत्था हो गये, उसकी बन्दूक छीन ली और उसे दबोच लिया, और साथ ही उन्होंने ग्रामीणों को उत्साहित किया कि वे शेष डाकुओं को बचकर न भागने दें। अन्ततः, वे सारी सम्पत्ति को वापिस लेने तथा डाकुओं के मुखिया को पकड़ने में सफल हो गये।

श्री धनपत सिंह की अपने पड़ोसियों की सम्पत्ति को बचाने के के लिये सशस्त्र डाकुओं से हुई मुठभेड़ साहस एवं वीरता का एक ज्वलन्त उदाहरण था।

सं० 3-प्रेज/68—राष्ट्रपति निम्नांकित व्यक्ति को उसकी उत्कृष्ट बहादुरी के लिये कीर्ति चक्र प्रदान करने का अनुमोदन करते हैं :—

श्री बिशाल सिंह,
ग्राम गौर,
छतरपुर जिला,
मध्य प्रदेश।

(मरणोपरान्त)

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—4 जनवरी, 1966)

4 जनवरी 1966, की रात को सशस्त्र डाकुओं ने मध्य प्रदेश के गौर ग्राम में ग्रामीणों को दूर रखने के लिये अन्धा-धुन्ध गोलियां चलाते हुये श्री महाराज सिंह के मकान पर धावा बोल दिया। जब श्री महाराज सिंह के दो लड़के सहायता के लिये चिल्लाये तो श्री बिशाल सिंह तथा कुछ अन्य ग्रामीण भागते हुए मकान की ओर आये। डाकुओं ने उनपर गोली चला कर श्री महाराज सिंह के एक लड़के तथा एक ग्रामीण को जख्मी कर दिया। इसकी परवाह न कर, श्री बिशाल सिंह और अन्य लोगों ने जो केवल लाठियां एवं बरछे लिये थे, शस्त्रों से अच्छी तरह से लेस डाकुओं का मुकाबिला किया। मुठभेड़ के दौरान श्री बिशाल सिंह तथा अन्य दो ग्रामीण मारे गये किन्तु दूसरे लोग अन्ततः एक डाकू को घेरने तथा उसे एक कमरे में बन्द करने में सफल हो गय। बाद में पुलिस मौके पर पहुंच गई और कमरे में बन्द डाकू को गिरफ्तार कर लिया।

श्री बिशाल सिंह ने, इस मुठभड़ में, जिसमें उन्हें अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा, उदाहरणीय साहस एवं दृढ़ निश्चय का परिचय दिया।

सं० 4-प्रेज/68—राष्ट्रपति निम्नांकित व्यक्तियों को उनकी वीरता के लिये शौर्य चक्र प्रदान करने का अनुमोदन करते हैं :—

1. श्री गम्भीर सिंह,
ग्राम गौर,
छतरपुर जिला,
मध्य प्रदेश। **(मरणोपरान्त)**

2. श्री हरि सिंह,
ग्राम गौर,
छतरपुर जिला,
मध्य प्रदेश।

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—4 जनवरी, 1966)

4 जनवरी, 1966 को रात को कुछ सशस्त्र डाकुओं ने मध्य प्रदेश के गौर ग्राम में ग्रामीणों को दूर रखने के लिये अन्धा-धुन्ध गोलियां चलाते हुये श्री महाराज सिंह के मकान पर धावा बोल दिया। श्री हरि सिंह पुत्र श्री महाराज सिंह तथा उनका भाई मकान से बाहर आने में सफल हो गये और सहायता के लिए चिल्लाये। एक ग्रामीण श्री गम्भीर सिंह कुछ अन्य ग्रामीणों के साथ डाकुओं से लड़ने में उनकी सहायता के लिये मकान की ओर दौड़े। डाकुओं ने फौरन

पर गोलियां चलाईं। मुठभेड़ के दौरान, श्री महाराज सिंह दो अन्य ग्रामीण मारे गये और सर्वश्री गम्भीर सिंह तथा हरि बुरी तरह जख्मी हो गये। श्री गम्भीर सिंह की बाद में अस्पताल त्यु हो गई। दूसरे ग्रामीणों ने बहादुरी से डाकुओं का सामना ा, जिन्होंने तब भागना शुरु कर दिया। अन्ततः, ग्रामवासी डाकू को घेरने तथा उसे एक कमरे में अंदरबन्द करने में समर्थ ये जहां बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।

सर्वश्री गम्भीर सिंह और हरि सिंह ने सशस्त्र डाकुओं से हुई ड़ में साहस एवं पहलशक्ति का जो प्रदर्शन किया वह अत्यन्त नीय था।

दिनांक 9 जनवरी 1968

सं० 5-प्रेस/68—राष्ट्रपति सीमा सुरक्षा दल के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिये राष्ट्रपति का पुलिस तथा अग्नि शमन सेवा पदक प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री नारायण सिंह,
निरीक्षक, 11वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा दल,

(भूतपूर्व 4थी बटालियन, राजस्थान सशस्त्र कांस्टेबुलरी)।

सेवाओं का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया।

23 सितम्बर, 1965 को पाकिस्तान के साथ युद्ध-विराम समझौते के पश्चात् पाकिस्तानी सेना भारतीय सीमा में घुस आई और जैसलमेर जिले में तनोत के समीप खाइयां बनाकर मोर्चे जमा लिये।

25 सितम्बर, 1965 की रात को निरीक्षक नारायण सिंह को उसकी कम्पनी की एक लड़ाकू गश्ती टोली के साथ पर्यवेक्षण के लिये भेजा। पाकिस्तानी सेना की शक्ति का अनुमान लगाने तथा उनके शस्त्रों आदि के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने के लिये श्री नारायण सिंह ने अपनी गश्ती टोली के साथ जानबूझ कर प्रयत्न किये कि पाकिस्तानी सेना गोलीबारी करे। 26 सितम्बर की सुबह 6 बजे पाकिस्तानी सेना ने छोटे शस्त्रों, 3" मार्टरों एवं मशीनी गनों से गोलीबारी शुरू कर दी। भारतीय गश्ती टोली के पास केवल राईफलें एवं ब्रेन गन थीं। यह देखते हुए कि शत्रु सेना संख्या एवं शस्त्रों में अधिक शक्तिशाली है, श्री नारायण सिंह ने अपनी कम्पनी को इस कठिन स्थिति से निकालने का निश्चय किया। उसने पाकिस्तानी सेना को अपनी एक प्लाटून से उलझा कर शेष कम्पनी को वापिस हटने में समर्थ बनाया। पाकिस्तानी सेना ने उसे घेरने का प्रयत्न किया और जब वे ग्रेनेड फेंकने की दूरी के अन्दर तक आने का प्रयत्न कर रहे थे तो श्री नारायण सिंह ने, अपनी छाती में गोली लगने से पहले, दो पाकिस्तानी सिपाहियों को मौत के घाट उतार दिया। घाव के बावजूद भी श्री नारायण सिंह धैर्य एवं शान्ति से अपने जवानों को उत्साहित करता हुआ उनका नेतृत्व करता रहा और चतुराई से खतरे के क्षेत्र से वापिस हटने में सफल हुआ। वह पाकिस्तानी सेना के सम्बन्ध में जानकारी लाये जो सैनिक अधिकारियों के लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण सिद्ध हुई।

इस कार्रवाई में श्री नारायण सिंह ने नेतृत्व एवं उच्च स्तर की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया और व्यक्तिगत शौर्य का एक प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत किया।

2. यह पदक राष्ट्रपति के पुलिस तथा अग्नि शमन सेवा पदक की नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 25 सितम्बर, 1965 से दिया जायेगा।

नागेन्द्र सिंह, राष्ट्रपति के सचिव

समाज कल्याण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 9 जनवरी 1968

संकल्प

सं० 14/1/67-एस० सी० टी० 11 (ए)—इस विभाग के संकल्प संख्या 14/1/67-एस० सी० टी० 11 दिनांक 28 नवम्बर, 1967 के पैरा 3 (बी) के अनुसरण में भारत सरकार निम्नलिखित दो व्यक्तियों को, इस विभाग के इसी संख्या के संकल्प दिनांक 28 नवम्बर, 1967 में बोर्ड पर नामित किए गए इक्कीस सदस्यों के अतिरिक्त, हरिजन कल्याण सम्बन्धी केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड के सदस्यों के रूप में नामित करती है :—

1. श्री महाबीर दास, संसद सदस्य।
2. श्री धर्म प्रकाश, संसद सदस्य।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि उक्त भारतीय राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

एन० सुन्दरम, संयुक्त सचिव

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय (कृषि विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 9 जनवरी 1968

संकल्प

सं० 7-14/67-सी० सी० 11—भारत सरकार के संकल्प संख्या 6-1/65-रिआर्ग (सी० सी०) दिनांक 16 अप्रैल, 1966 के अनुसार भारतीय तिलहन विकास परिषद् को पुनर्गठित करने का निश्चय किया गया है। पुनर्गठित परिषद् का गठन निम्न प्रकार होगा :

1. अध्यक्ष	परिषद् में उत्पादकों के प्रतिनिधियों में से एक को भारत सरकार द्वारा नामजद किया जायेगा।
2. उपाध्यक्ष	सचिव, कृषि विभाग, भारत सरकार।
3. सदस्य	
(क) केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के प्रतिनिधि	(1) कृषि विभाग में प्रत्येक राज्य सरकार के एक एक प्रतिनिधि को निम्नलिखित सरकारों द्वारा नामजद किया जाए :—

(1) गुजरात
(2) मद्रास
(3) उत्तर प्रदेश
(4) आन्ध्र प्रदेश
(5) महाराष्ट्र

(6) मैसूर
(7) मध्य प्रदेश

(2) योजना आयोग का एक प्रतिनिधि ।

(3) कृषि आयुक्त, भारत सरकार ।

(4) वाणिज्य मन्त्रालय का एक प्रतिनिधि

(5) महा निदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् अथवा उनका नामज़द किया हुआ व्यक्ति ।

(ख) उत्पादकों के प्रतिनिधि

(1) उत्पादकों का एक प्रतिनिधि निम्नलिखित सरकारों द्वारा नामज़द किया जायेगा :—
(1) गुजरात
(2) मद्रास
(3) उत्तर प्रदेश
(4) आन्ध्र प्रदेश
(5) महाराष्ट्र
(6) मैसूर
(7) मध्य प्रदेश
(8) पंजाब
(9) हरियाना

(2) उत्पादकों का एक प्रतिनिधि भारत सरकार द्वारा नामज़द किया जाए ।

(ग) उद्योग के प्रतिनिधि

प्रत्येक का एक एक प्रतिनिधि :
(1) वनस्पति मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन
(2) खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड
(3) इण्डियन आयल मिलर्स एसोसिएशन ।

(घ) व्यापार के प्रतिनिधि

व्यापार के तीन प्रतिनिधि फैडरेशन आफ इण्डियन चैम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इन्डस्ट्री द्वारा नामज़द किये जाना ।

(ङ) संसद् सदस्य

संसदीय मामलों के विभाग की सलाह से भारत सरकार द्वारा नामज़द 5 संसद सदस्य :—
(1) श्री जतिन्द्र नाथ प्रमाणिक
(2) श्री के० अन्बाझगन
(3) श्री कीकर सिंह
(4) श्री एन० टी० दास
(5) डाक्टर अमृतराव जी सोनार

(च) समय समय पर सरकार द्वारा नामज़द किये गये ऐसे अतिरिक्त व्यक्ति जो परिषद् में उन हितों का प्रतिनिधित्व करेंगे जिनके लिये कोई भी प्रतिनिधि पहले से नहीं है ।

4. सदस्य सचिव — निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, तिलहन विकास, खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मन्त्रालय (कृषि विभाग) ।

5. प्रेक्षक — (जो परिषद् के सदस्य तो नहीं होंगे किन्तु परिषद् के कार्यों में सहायता देने के लिये उन्हें निरापवाद रूप से आमंत्रित किया जाएगा) ।

(1) कृषि विपणन सलाहकार, खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मन्त्रालय (कृषि विभाग)

(2) खाद्य और कृषि मन्त्रालय से सम्बन्धित संयुक्त सचिव (वित्त)

(3) अर्थ तथा अंक सलाहकार, खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मन्त्रालय (कृषि विभाग)

(4) वनस्पति रक्षा सलाहकार, भारत सरकार

(5) उप आयुक्त (निर्यात वृद्धि), खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मन्त्रालय (कृषि विभाग)

(6) राष्ट्रीय बीज निगम का एक प्रतिनिधि

2. यह परिषद् एक सलाहकार निकाय होगी और उसके निम्नलिखित कार्य होंगे :—

(1) केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए तिलहन विकास कार्यक्रमों पर समय समय पर विचार करना ।

(2) निर्धारित लक्ष्यों के सम्बन्ध में तिलहन विकास की प्रगति पर विचार तथा पुनर्विलोकन करना ।

(3) जहां आवश्यकता हो वहां विकास कार्यक्रमों/योजनाओं की गति को तीव्र करने के लिए उपायों की सिफारिश करना ।

(4) तिलहन, विपणन तथा व्यापार, जिसमें मूल्य नीति भी शामिल है, की समस्याओं पर पुनर्विचार करना और सुधार के लिए सुझाव देना ।

(5) अन्य कार्य जो भारत सरकार द्वारा समय समय पर परिषद् को सौंपे जायें ।

3. उत्पादन क्षेत्रों में स्थित व्यापार तथा उद्योग के प्रमुख केन्द्रों में परिषद् समय समय पर अपनी बैठक किया करेगी और भारत सरकार को इस सम्बन्ध में अपनी सिफारिश किया करेगी ।

4. परिषद् के सदस्यों की अवधि 3 वर्षों के लिए होगी परन्तु आवश्यकता होने पर भारत सरकार उसे बढ़ा सकती है ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति समस्त राज्य सरकारों, संघ क्षेत्रों और भारत सरकार के समस्त मन्त्रालयों, योजना आयोग, मन्त्रिमण्डल सचिवालय, लोक सभा तथा राज्य सभा सचिवालयों को भेजी जाए।

एस० जे० मजुमदार, अतिरिक्त सचिव

शिक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 9 दिसम्बर 1967

संकल्प

विषय : तकनीकी शिक्षा के लिए अखिल भारतीय परिषद

सं० एफ० 1-1/67 टी-2—भारत सरकार ने पूर्ववर्ती शिक्षा विभाग के संकल्प संख्या एफ 16/10/44 ई० 3, तारीख 30 नवम्बर, 1945 जिस रूप में उसे समय-समय पर (14 अप्रैल, 1967 तक) संशोधित किया गया है, के आंशिक आशोधन में राष्ट्रपति ने आदेश दिया है कि परिषद के संविधान से संबंधित उपरिलिखित संकल्प के पैराग्राफ 3(i) के खण्ड (टी) के बाद निम्नलिखित खण्ड जोड़ दिया जाए :—

(यू) सदस्य-सचिव।

राष्ट्रपति का यह आदेश भी है कि उपरोक्त संकल्प के पैरा 5 में 'सचिव' शब्द जहां भी आया हो उसे 'सदस्य-सचिव' पढ़ा जाए।

आदेश है कि संकल्प को भारत राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

आदेश है कि प्रति सभी राज्य सरकारों, केन्द्र शासित क्षेत्रों तथा भारत सरकार के मंत्रालयों को भेजी जाए।

एल० एस० चन्द्रकान्त, संयुक्त सलाहकार, शिक्षा (तकनीकी)

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, दिनांक 5 जनवरी 1968

संस्ताव

पत्तन

सं० 8-बी० जी० (204)/67—भारत सरकार की बम्बई पत्तन की 1966-67 की प्रशासनिक रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। रिपोर्ट की मुख्य बातों का विहंगावलोकन नीचे किया जाता है :—

2. **वित्तीय स्थिति** : विचाराधीन वर्ष में पोर्ट ट्रस्ट का कुल राजस्व 2077.71 लाख रुपये था। पिछले वर्ष यह संख्या 2064.33 लाख रुपये थी। 1966-67 में कुल व्यय 1883.41 लाख रुपये का हुआ। 1965-66 में यह संख्या 1692.99 लाख रुपये थी। इस प्रकार 194.30 लाख रुपये का अधिशेष रहा। व्यय में वृद्धि मुख्यतः इन शीर्षकों के अधीन हुई, सामान्य प्रभार, गीली गोदी, भूमि और भवन तथा रेलवे और कर्मचारियों में वृद्धि, महंगाई भत्ता, दूसरी अन्तरिम सहायता की अदायगी, वेतन-मान के पुनरीक्षण के कारण बकाया की अदायगी, बोनस के स्थान पर अनुग्रह पूर्वक अदायगी, बालकों की शिक्षा सहायता योजना।

1966-67 के अन्त में पोर्ट ट्रस्ट आरक्षित निधि में 39.39 करोड़ रुपये शेष थे। 14.56 करोड़ रुपये के शेष ऋण में से, 5.68 करोड़ रुपये सार्वजनिक देयता के थे और सरकार के 7.91 करोड़ रुपये थे। 0.97 करोड़ रुपये का शेष ट्रस्टियों द्वारा रखे गये आन्तरिम ऋण की राशि थी। ऋण की पुनर्अदायगी के लिये ट्रस्टियों ने 6.25 करोड़ के शेष को सामान्य शोधन निधि में और 3.12 करोड़ रुपये मरीन आयल टरमिनल के लिये सरकार से लिये ऋण की पुनर्अदायगी के लिये निलंबित खाते में रखा है।

3. **यातायात** : 1966-67 में पत्तन में 18266000 के कुलटन भार को धरा उठाई की गई, जिसमें से आयात की राशि 13227000 और निर्यात की 5039000 टन थी। पिछले वर्ष की आयात और निर्यात की संख्या में क्रमशः 12976000 और 5140000 टन थी जिनका जोड़ 18116000 टन था।

वर्ष में धरा उठाई किये गये सम्पूर्ण यातायात की संख्या पत्तन के लिये सर्वोच्च रिकार्ड संख्या थी।

1966-67 में 123761 समुद्रपार यात्रियों ने पत्तन व्यवहृत किया। तटीय यात्रियों की संख्या 633475 थी।

4. **नौवहन** : 1966-67 में पत्तन में प्रवेश करने वाले पोतों की संख्या 3062 थी जो 12.00 मिलियन कुल पंजीकृत टनों के थे। 1965-66 में ये योजनाएं 2958 पोत और 21.72 मिलियन टन थी। इस वर्ष पत्तन में जो सबसे बड़ा पोत आया वह 38621 कुलटनभार का वा० पो० "राटरडेम" था।

1966-67 में पत्तन की व्यवहृत करने वाले पालपोतों की संख्या 33528 थी। 1965-66 में इस प्रकार के पोतों की संख्या 34329 थी।

1966-67 में 113 पोतों ने सूखी गोदियों का व्यवहार किया। मरम्मत के प्रयोजनों के लिए गीली गोदियों में घाट पर लगाये गये पोतों की संख्या 73 थी जिसमें अलेक्जेन्ड्रा डाक पर घाटित किये गये 15 पोत भी शामिल हैं।

5. **निर्माण-कार्य** : पूंजीखाते पर कुल व्यय 453.99 लाख रुपय किया गया। 1966-67 में जिन महत्वपूर्ण कार्यों पर व्यय किया गया उनमें से कुछ ये हैं:—

क्रम संख्या	कार्य का नाम	व्यय (लाख में)
1.	गोदी विस्तार स्कीम	188.40
2.	मुख्य पत्तन जलमार्ग का निकर्षण मुख्य योजना, क्रम 1 तथा 2	22.46
3.	पत्तन के विकास के लिय मास्टर योजना को तैयार करना।	16.86
4.	30 चन क्षमता की 2 मोबाइल क्रेनों की खरीद	18.37
5.	4. पत्तन टगों की खरीद	103.90
6.	पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारियों के लिये अस्पताल की इमारत	13.21
7.	ब्लाडंपियर विस्तार, और क्रेनों तथा अन्य सेवाओं सहित यात्रा तथा माल सीमांत भवन	12.79

6. पोर्ट ट्रस्ट रेलवे

1965-66 की तुलना में ट्रंक यातायात की मात्रा में कमी रही। यह निम्न सारिणी से स्पष्ट हो जायेगा :—

	डिब्बे		टन
	आवक	जावक	
1965-66	111,230	151612	5026077
1966-67	95,443	151534	4834300

1965-66 तथा 1966-67 में बंबई पोर्ट ट्रस्ट रेलवे के कामकाज के परिणाम, जैसा ट्रस्टियों द्वारा अनुमोदित पुनरीक्षित पद्धति के अनुसार कार्यान्वित किया गया है, नीचे दिया जाता है :—

	राजस्व	व्यय	अधिशेष (+)
	(संख्या लाख रुपयों में)		कमी (—)
1965-66	130.44	177.04	(—) 46.61
1966-67	138.33	198.67	(—) 60.34

वित्तीय स्थिति के खराब होने का कारण यह था कि भाड़े साइडिंग प्रभारों और सीमान्त शुल्कों में हुई थोड़ी वृद्धि शंटिंग, रिबुकिंग और विशाखन में हुई कमी में विलीन हो गई तथा व्यय में वृद्धि हुई जिसका मुख्यकारण महंगाई भत्ते की दरों में वृद्धि, अतिरिक्त अन्तरिम सहायता देना, बोनस के स्थान पर अनुग्रहपूर्वक अदायगी, शिक्षण फीस की वापसी, बालक शिक्षा भत्ते की अदायगी तथा स्थायी पद सामग्री की लागत में वृद्धि होने के कारण सिब्बन्दी लागत में वृद्धि हुई।

7. नौवहन का विरामकाल पोतों के लादने/उतारने की गति :

15 मार्च 1967 को समाप्त हुए पखवाड़े में 1966-67 में गोदी व्यवहृत करने वाले पोतों की सर्वोच्च संख्या 101 थी। उक्त पखवाड़े में औसत विरामकाल 4.1 दिन था। इसके विपरीत 31 जुलाई 1966 को समाप्त हुये पखवाड़े में 7 दिनों का कम से कम विरामकाल था जबकि 60 पोतों ने गोदी व्यवहृत की।

1966-67 में पोतों के उतारने और लादने की गति 1000 टन और इसके अधिक थी जैसा नीचे दिखाया गया है :—

	टनों में विरामकाल की प्रतिदिन की सबसे अधिक औसत दर	
	1965-66	1966-67
उतारना (आयात)	2844	2954
लादना (निर्यात)	3012	2614

कार्यदर स्कीम के अधीन धरा उठाई किया गया माल 1966-67 में मापतौल से 127 प्रतिशत अधिक था।

8. राज संपत्ति विभाग:—सब स्रोतों से राज संपत्ति विभाग का राजस्व 216.95 लाख रुपया था। (इसमें गोदी विभाग द्वारा एकत्रित 14.86 लाख रुपया शामिल नहीं है)। 1965-66 में यह संख्या 139.90 लाख रुपये थी।

9. श्रम :—इस वर्ष पत्तन में औद्योगिक संबंध समान्यतया सन्तोषजनक रहे। पत्तन के कल्याणकारी कामों में कई क्रियाकलाप शामिल रहे, जैसे, खेलकूद, मनोरंजन, विभिन्न आमोद प्रमोद, यात्रा, वर्जीफे, कान्टीन साधारण डाक्टरी देखभाल, स्त्रियों का चिकित्सालय, वाचनालय और पुस्तकालय इत्यादि। कर्मचारियों की कल्याणकारी निधि में राजस्व से 3.79 लाख रुपये का अंशदान दिया गया।

10. कर्मचारी :—1966-67 में कर्मचारियों पर 1040.05 लाख रुपये व्यय किये गये। पिछले वर्ष ये संख्या 914.10 लाख रुपये थी। 125.95 लाख रुपय की यह वृद्धि अधिकारियों के वेतन भाग के पुनरीक्षण के कारण उन्हें बकाये की अदायगी, बोनस के स्थान पर अनुग्रहपूर्वक अदायगी को दिया जाना, तीसरी और चौथी श्रेणियों क कर्मचारियों को दूसरी अन्तरिम सहायता, महंगाई भत्ते का पुनरीक्षण, शिक्षा सहायता की स्कीम को लागू करना, अतिरिक्त कर्मचारी इत्यादि के कारण हुई।

1966-67 में डाक्टरी सहायता में 12.34 लाख रुपये का कुल व्यय किया गया पिछले वर्ष यह राशि 10.14 लाख रुपये थी।

11. अभिस्वीकृति

पोर्ट ट्रस्ट ने उपयोगी कार्य कर एक और वर्ष पूरा किया और भारत सरकार को उससे सन्तोष है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संस्ताव की एक प्रतिलिपि समस्त संसद को भेज दी जाये।

यह आदेश दिया जाता है कि सामान्य सूचना के लिये यह संस्ताव भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाये।

जेड० एस० आगा, संयुक्त सचिव

सिंचाई व बिजली मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 6 जनवरी, 1968

संकल्प

सं० वि० का०—5—510 (3)/65—घड़ी गंडक नदी से होने वाली तबाही से चितौनी बांध की सुरक्षा के लिये दीर्घकालीन उपायों को बताने के लिये स्थापित की गई तकनीकी समिति द्वारा अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अवधि को भारत सरकार इस मंत्रालय के संकल्प सं० वि० का०—5—510(3)/65, दिनांक 28—5—65, 24—8—65, 21—3—66, 16—7—66, 19—11—66, 26—5—67 और 17—7—67 के सांतत्य में 29 फरवरी, 1968 तक बढ़ाती है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति उत्तर प्रदेश और बिहार की राज्य सरकारों को सूचनार्थ भेजी जए।

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र म प्रकाशित कर दिया जाये और उत्तर प्रदेश तथा बिहार की राज्य सरकारों से प्रार्थना की जाए कि वे इस संकल्प को राज्य के राजपत्र में आम सूचना के लिये प्रकाशित कर दें।

पी० आर० आहूजा, संयुक्त सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 8 जनवरी 1968

संकल्प

संख्या 33(4)/67—डी० डब्ल्यू०—1—चम्बल नियंत्रण बोर्ड के संस्थापन से सम्बद्ध, समयानुसार संशोधित इस मंत्रालय के संकल्प संख्या एफ० 11(2)/54—डी० डब्ल्यू०—1 दिनांक 14 अप्रैल 1955 के पैरा 3, आलेख 1 के पश्चात निम्नलिखित आलेख को रख दिया जाए :—

(2) सिंचाई व बिजली उपमंत्री, भारत सरकार....सदस्य

आलेख (2) से (17) को पुनः क्रमांकित कर (3) से (18) कर दिया जाए।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकारों, वित्त मंत्रालय और योजना आयोग के पास भेज दिया जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए और मध्य प्रदेश और राजस्थान की सरकारों से प्रार्थना की जाए कि वे भी आम सूचना के लिये इस को राज्यों के राजपत्रों में प्रकाशित कर दें।

के० एस० एस० मूर्ति, उप-सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 8th January 1968

No. 2-*Pres.*/68.—The President is pleased to approve the award of the ASHOK CHAKRA for most conspicuous bravery to :—

1. Shri Hukum Singh,
   Village Gour,
   Chhatarpur District,
   Madhya Pradesh.
2. Shri Lakhan Singh,
   Village Gour,
   Chhatarpur District,
   Madhya Pradesh.
3. Shri Govind Singh,
   Village Gour,
   Chhatarpur District,
   Madhya Pradesh.
4. Shri Takhat Singh,
   Village Gour,
   Chhatarpur District,
   Madhya Pradesh. (*Posthumous*)

(*Effective date of the award—4th January* 1966).

On the night of 4th January, 1966, armed dacoits firing indiscriminately to keep away the villagers raided the house of Shri Maharaj Singh in village Gour in Madhya Pradesh. Shri Govind Singh, son of Shri Maharaj Singh, and his brother managed to come out of the house and shouted for help. A number of villagers including Sarvashri Hukum Singh, Lakhan Singh and Takhat Singh came to the rescue. The dacoits fired at them injuring a villager and Shri Govind Singh's brother. Undaunted, the villagers, carrying only lathis and spears, faced the dacoits who were well-equipped with fire arms. Shri Govind Singh scaled over the wall of the house and jumped about 10 feet down into the courtyard where his father had been tide with a rope and was being tortured. He, along with Shri Takhat Singh, threw themselves upon the dacoits who fired at them. During the encounter, Sarvashri Maharaj Singh, Takhat Singh and two other villagers were killed and Shri Govind Singh and his brother were seriously injured. Despite this, Shri Hukum Singh and Shri Lakhan Singh fought their way into the house and cornered two of the dacoits. One of them managed to escape through a hole bored in the tiled roof of the room but they succeeded in trapping and locking up the other dacoit inside a room. By that time the other dacoits became unnerved and started running away. In the meantime the Police reached the spot and arrested the dacoit who was locked inside the room and subsequently arrested some more dacoits who had fled.

The gallant action of Sarvashri Hukum Singh, Lakhan Singh, Govind Singh and Takhat Singh in fighting against armed dacoits was a shining example of gallantry and courage.

5. Shri Dhanpat Singh,
   Village Kharehta,
   Jabalpur District,
   Madhya Pradesh.

Effective date of the award—27th February 1967)

On the night of 27th February, 1967, armed dacoits raided the house of Shri Daduram in village Kharehta in Madhya Pradesh. Shri Daduram and his wife were mercilessly beaten and tortured to force them to reveal where their valuables were kept. After some time Shri Daduram became unconscious and his wife ponited to where the ornaments were in the house. Meanwhile their neighbour in the adjoining house heard the noise and attempted to peep through the window and flashed his torch. The dacoits fired at him but he managed to escape and informed the villagers. Shri Dhanpat Singh, who was staying nearby, heard the gun fire. He at once grabbed his lathi and rushed out asking people who had started collecting to follow him. The dacoits started firing indiscriminately and some villagers ran way. Shri Dhanpat Singh rallied the villagers and advanced to the House. The dacoits, who were throttling Shri Daduram's wife to make her reveal the location of other property, got frightened and made off with property worth Rs. 40,000. Shri Dhanpat Singh, along with others, chased the dacoits. The dacoits opened fire injuring a villager. Undaunted, Shri Dhanpat Singh, armed only with a lathi, pounced upon the ring leader who was carrying a 12 bore gun. He, with the help of a villager, grappled with the dacoit, snatched his weapon away and overpowered him, and at the same time he urged the villagers not to allow the remaining dacoits to escape. Ultimately, they succeeded in retrieving the entire property and capturing the leader of the dacoits.

Shri Dhanpat Singh's fight against armed dacoits in defence of his neighbour's property was a shining example of courage and gallantry.

No. 3-*Pres.*/68.—The President is pleased to approve the award of the KIRTI CHAKRA for act of conspicuous gallantry to :—

Shri Bishal Singh,
Village Gour,
Chhatarpur District,
Madhya Pradesh. (*Posthumous*)

(*Effective date of award—4th January* 1966)

On the night of 4th January, 1966, armed dacoits firing indiscriminately to keep away the villagers raided the house of Shri Maharaj Singh in village Gour in Madhya Pradesh. When Shri Maharaj Singh's two sons shouted for help, Shri Bishal Singh and some other villagers came running towards the house. The dacoits fired at them injuring one of the sons of Shri Maharaj Singh and a villager. Undaunted, Shri Bishal Singh and others, armed only with lathis and spears, faced the dacoits who were well-equipped with fire arms. During the encounter, Shri Bishal Singh and two other villagers were killed, but the others ultimately succeeded in trapping and locking up a dacoit inside a room. Later the Police reached the scene and arrested the dacoit who was locked inside the room.

Shri Bishal Singh displayed exemplary courage and determination in this encounter in which he lost his life.

No. 4-*Pres.*/68.—The President is pleased to approve the award of the SHAURYA CHAKRA for acts of gallantry to :—

1. Shri Gambhir Singh,
   Village Gour,
   Chhatarpur District,
   Madhya Pradesh. (*Posthumous*)
2. Shri Hari Singh,
   Village Gour,
   Chhatarpur District,
   Madhya Pradesh.

(Effective date of award—4th January 1966)

On the night of 4th January, 1966, some armed dacoits firing indiscriminately to keep away the villagers raided the house of Shri Maharaj Singh in village Gour in Madhya Pradesh. Shri Hari Singh, son of Shri Maharaj Singh, and his brother managed to come out of the house and shouted for help. Shri Gambhir Singh, a villager, accompanied by some other villagers, came running towards the house to help fight the dacoits. The dacoits immediately opened fire at them. During the encounter, Shri Maharaj Singh and two other villagers were killed and Sarvashri Gamghir Singh and Hari Singh were seriously injured. Shri Gambhir Singh subsequently died in hospital. The other villagers continued to face the dacoits boldly who then started running away. Ultimately, the villagers were able to trap a dacoit and lock him up inside a room, where he was later arrested by the Police.

The courage and initiative displayed by Sarvashri Gambhir Singh and Hari Singh in fighting the armed dacoits were highly commendable.

The 9th January 1968

No. 5-Pres./68.—The President is pleased to award the President's Police and Fire Services Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Border Security Force :—

Name of the officer and rank

Shri Narain Singh,
Inspector, XIth Battalion,
Border Security Force.
(lately IV Battalion, Rajasthan Armed Constabulary).

Statement of services for which the decoration has been awarded.

After the Cease-fire Agreement with Pakistan on the 23rd September, 1965, the Pakistani troops entered the Indian territory and entrenched themselves near Tanot in Jaisalmer District.

On the night of 25th September, 1965 Inspector Narain Singh was sent with a fighting patrol of his Company on a reconnaisance. In order to assess the strength of the Pakistani forces and to get intelligence about their weapons, etc. Shri Narain Singh, with his patrol, made efforts deliberately to draw the fire of Pakistani forces. The latter started firing at 0600 hours on 26th September with small arms as well as 3" mortars and medium machine guns. The Indian patrol had only rifles and Bren guns. Seeing that the enemy forces were much superior in number and firepower, Shri Narain Singh decided to extricate his Company from this difficult position. He engaged the Pakistani forces with one of his platoons and thus enabled the rest of his Company to withdraw. The Pakistani forces tried to encircle him and when they were trying to close within the grenade throwing distance, Shri Narain Singh himself killed two Pakistani soldiers before receiving a bullet wound in his chest. Despite this wound, Shri Narain Singh remained in command and encouraging his men in a cool and calm manner, succeeded in tactically withdrawing out of the danger zone. He brought information regarding the Pakistani forces which proved of great value to the Army authorities.

In this action Shri Narain Singh displayed leadership and devotion to duty of a high order and set an inspiring example of personal bravery.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the President's Police and Fire Services Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 25th September, 1965.

NAGENDRA SINGH, Secy. to the President

DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE

RESOLUTION

New Delhi, the 9th January 1968

No. 14/1/67-*SCT.II(A)*.—In pursuance of paragraph 3(b) of this Department's Resolution No. 14/1/67-SCI.II dated the 28th November 1967, the Government of India nominates the following two persons as members of the Central Advisory Board for Harijan Welfare in addition to the twentyone members nominated on the Board in this Department's resolution of even number, dated the 28th November, 1967 :

1. Shri Mahabir Das, M.P.
2. Dr. Dharam Prakash, M.P.

ORDER

ORDERED that the above be published in the Gazette of India.

N. SUNDARAM, Jt. Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 12th January 1968

No. 8/22/67-*CS-II*—The following amendments to the Rules for the Clerks' Grade Examination 1968, published under the Ministry of Home Affairs Notification No. 8/22/67-CS-II, dated the 25th November, 1967, are published for general information :—

S. No.	Reference	Amendment to be made
1	2	3
1.	Page 868, col. 1, para 5(b)(iii), 1st line.	The first line should be ***substituted*** by the words "(iii) up to a maximum of eight years if a candidate be".
2.	Page 868, col. 1, para 5(c), 2nd line.	The word "appointed" may be ***inserted*** between words "regularly" and "as".
3.	Page 870, col. 2, subdivision 'B' para b(ii), 1st line.	"Rs. 110" may be substituted *for* "Rs. 100".
4.	Page 871, col. 1, paras 3, 4 and 5.	Para 3 has been omitted. It should be ***inserted*** as follows :— "3. Lower Division Clerks will be eligible for confirmation and promotion in accordance with the rules in force from time to time". The remaining paras 3 and 4 should be renumbered as 4 and 5.

The 13th January 1968

No. 8/1/67-*CS-II*.—The Ministry of Home Affairs Notification No. 8/20/66-CS-II, dated the 25th June, 1966, published in the Gazette of India dated 25-6-1966, relating to the Upper Division Grade Departmental Competitive Examination, 1966, is hereby cancelled.

MANGLI PRASAD, Dy. Secy.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

RESOLUTION

New Delhi, the 12th January 1968

No. F. 7(2)-*Ins.II*/67.—In partial modification of the Ministry of Finance Resolution No. 7(2)-Ins.II/67, dated the 21st July, 1967 setting up a Committee to investigate into the causes of the present high level of expenses of the Life Insurance Corporation of India, it has been decided to extend by six months the period of submission of the Committee's report. The Committee will accordingly report to the Government by the 20th July, 1968 instead of the 20th January, 1968.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

RAJ K. NIGAM, Dy. Secy.

MINISTRY OF COMMERCE

RESOLUTIONS

New Delhi-11, the 6th January 1968

No. 1(6)/67-*HC*.—The Government of India have decided to nominate Shri V. N. Kak, a non-official member of the All India Handcrafts Board as re-constituted *vide* this Ministry's Resolution No. 1/6/67-HC dated the 16th September, 1967 with immediate effect.

2. The term of office of Shri V. N. Kak will be the same as for other non-official members of the Board.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all concerned and that it be published in the Gazette of India.

The 12th January 1968

No. 19/6/66-*KVI(P)*.—In partial modification of the Government of India in the Ministry of Commerce Resolution No. 19/6/66-KVI(P), dated the 8th June, 1966, as amended *vide* Resolutions No. 19/6/66-KVI(P), dated the 12th August, 1966, 4th Oct., 1966, 5th April, 1967 and 29th July, 1967, the Government of India have decided, in view of the volume of work involved and the progress made so far, to extend by two months the period for submission of the Report by the Khadi & Village Industries Committee. The following may, therefore, be substituted for paragraph 4 of the Government of India Resolution No. 19/6/66-KVI(P) dated the 8th June, 1966, as amended :—

"4. The Committee is requested to submit its Report to Government by the 29th February, 1968."

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be published in the Gazette of India for general information and that it be communicated to all.

P. SITARAMAN, Dy. Secy.

MINISTRY OF HEALTH, FAMILY PLANNING AND URBAN DEVELOPMENT

(Department of Family Planning)

RESOLUTION

New Delhi, the 6th January 1968

No. 5-1/67-*MCH*.—On the expiry of the term of the Advisory Committee of the Countess of Dufferin's Fund as constituted *vide* Ministry of Health letter No. F. 6-7/64-ME dated the 3rd March, 1965, the Government of India have decided to re-constitute the Committee with immediate effect. The composition of the re-constituted Committee shall be as follows :—

Chairman

1. Minister of State for Health, Family Planning and Urban Development.

Members

2. Smt. Ganga Devi, M.P. (Lok Sabha).
3. Smt. P. J. Mehta, M.P. (Rajya Sabha).
4. Director General of Health Services.
5. Deputy Secretary (P) Department of Family Planning.
6. Deputy Financial Adviser (Health) (A representative of the Ministry of Finance).

Member-Secretary

7. Adviser (M.C.W.), Department of Family Planning.

2. The terms of reference of the Committee will be to advise the Central Government in the matter of utilisation and administration of the income from the Countess of Dufferin's Fund.

3. The life of the Committee as a whole will be two years. The members of Parliament appointed as members of the committee shall cease to be members of the Parliament earlier.

K. N. SRIVASTAVA, Jt. Secy.

MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION

(Department of Agriculture)

New Delhi-1, the 9th January 1968

RESOLUTION

No. 7-14/67-*C.C.II*.—It has decided to reconstitute the Indian Oilseeds Development Council set up *vide* Government of India's Resolution No. 6-1/65-Reorgn.(CC) dated the 16th April, 1966. The reconstituted Council will consist of the following :—

I. *Chairman*

One of the growers' representative on the Council to be nominated by the Government of India.

II. *Vice-Chairman*

The Secretary to the Government of India in the Department of Agriculture.

III. *Members*

(a) *Representatives of the Central and State Governments*

(1) One representative each of the State Government in the Department of Agriculture to be nominated by the Governments of :—
(i) Gujarat.
(ii) Madras.
(iii) Uttar Pradesh.
(iv) Andhra Pradesh.
(v) Maharashtra.
(vi) Mysore.
(vii) Madhya Pradesh.

(2) One representative of the Planning Commission.

(3) Agricultural Commissioner with the Government of India.

(4) One representative of the Ministry of Commerce.

(5) Director General, Indian Council of Agricultural Research or his nominee.

(b) *Growers' representatives*

(1) One representative of the growers each to be nominated by the Governments of :—
(i) Gujarat.
(ii) Madras.
(iii) Uttar Pradesh.
(iv) Andhra Pradesh.
(v) Maharashtra.
(vi) Mysore.
(vii) Madhya Pradesh.
(viii) Punjab.
(ix) Haryana.

(2) One representative of growers to be nominated by the Government of India.

(c) *Representatives of Industry*

One representative each of :—

(i) The Vanaspati Manufacturers Association.
(ii) Khadi and Village Industry Board.
(iii) Indian Oil Miillers Association.

(d) *Representatives of Trade*

Three representatives of trade to be nominated by the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry.

(e) *Members of Parliament*

Five Members of Parliament nominated by the Government of India in consultation with the Department of Parliamentary Affairs :—

1. Shri Jatindra Nath Pramanik.
2. Shri K. Anbazhagan.
3. Shri Kikar Singh.
4. Shri N. T. Das.
5. Dr. Amritrao G. Sonar.

(f) Such additional persons as may, from time to time, be nominated by the Government of India to represent interest(s) not already represented in the Council.

IV. *Member-Secretary*

The Director, Regional Office, Oilseeds Development, Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Department of Agriculture).

V. *Observers*

(Who would not be members of the Council but would be invariably invited to assist the Council in its deliberations).

(1) Agricultural Marketing Adviser, Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Department of Agriculture).

(2) Joint Secretary (Finance) accredited to the Ministry of Food and Agriculture.

(3) Economic & Statistical Adviser, Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Department of Agriculture).

(4) Plant Protection Adviser to the Government of India.

(5) Deputy Commissioner (Export Promotion) Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Department of Agriculture).

(6) A representative of the National Seed Corporation.

(2) The Council will be an advisory body and will have the following functions :—

(i) to consider, from time to time, the oilseeds development programmes formulated by the Central and State Governments;

(ii) to consider and review the progress of oilseeds development in the context of targets laid down;

(iii) to recommend measures for accelerating the tempo of development programmes/schemes, wherever necessary;

(iv) to consider and review the problems of oilseeds marketing and trade, including price policy, and to make suggestions for improvement; and

(v) any other functions which may, from time to time, be assigned by the Government of India to the Council.

3. The Council will meet periodically in important centres of trade and industry, in areas in which oilseeds are grown and will make its recommendations to the Government of India.

4. The term of the members of the Council will be for three years. It may, however, be extended by the Government of India, wherever considered necessary.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all State Governments, Administrations of Union Territories and Ministries of the Government of India, Planning Commission, Cabinet Secretariat, Lok Sabha and Rajya Sabha Secretariat.

S. J. MAJUMDAR, Additional Secy.

(Department of Food)

New Delhi, the 9th January 1968

(FAMINE)

No. 3-6/67-*SR.*—In pursuance of the provision of the Bye-law 7 made under Rule 7 of the Rules for the Administration of the Indian People's Famine Trust, the Central Government are pleased to publish the audited accounts of receipts, disbursements and assets of the Indian People's Famine Trust for the period from 1st July, 1966 to 30th June, 1967, as below.

S. BANSI, Under Secy.

SCHEDULE I

INDIAN PEOPLES' FAMINE TRUST

Statement showing details of Assets at the close of 30-6-1967

1. Endowment Fund in Govt. Securities vested in Treasurer, Charitable Endowments, West Bengal 3% Conversion loan of 1946 (Face Value)		Rs. 32,78,400.00
2. Cash and deposits with the State Bank of India, New Delhi, as on 30-6-1967		
(a) Fixed Deposit for one year @ 6% per annum.		
(i) Receipt No. 664148 dt. 1-8-66	Rs. 25,000.00	
(ii) Receipt No. 664149 dt. 1-8-66	Rs. 25,000.00	
(iii) Receipt No. 664150 dt. 1-8-66	Rs. 25,000.00	
	Rs. 75,000.00	
(b) Cash in Current Account.	Rs. 4,388.31	
		Rs. 33,57,788.31

NEW DELHI.
Dated 15-7-1967.

BISHAN CHAND, Honorary Secy.
Checked and found correct.
D. D. DHINGRA, Accountant General, Central Revenues, New Delhi.

SCHEDULE II

INDIAN PEOPLES' FAMINE TRUST

Abstract Account of Receipts and Disbursements during the period from 1-7-66 *to* 30-6-67

RECEIPTS	Rs.	Rs.	DISBURSEMENTS	Rs.	Rs.
Opening Balance :			1. *Payment of grants:*		
1. Fixed Deposits for 1 year	75,000·00				
Fixed Deposits for 91 days	75,000·00		(1) West Bengal	25,000·00	
Deposit at call	25,000·00		(2) Rajasthan	20,000·00	
Current Account	346·35	1,75,346·35	(3) Madras	25,000·00	

2. Interest on Endowment Fund of Rs. 32,78,400·00 Interest 98,352·00 Less Fee recovered at Source by Treasurer, Charitable endowment Rs. 983·52		97,368·48
3. Refunds of unspent balance — Gujarat (11/64) 760·00 Rajasthan (6/66) .. 11·20		771·20
4. Interest on Fixed and Short Term Deposits		6,369·78
TOTAL ...		2,79,855·81

Checked and found correct.

D. D. DHINGRA
Accountant General Central Revenue, New Delhi

MINISTRY OF EDUCATION
(Technical Division)

RESOLUTION

New Delhi-1, the 9th January 1968

SUBJECT :—*All India Council for Technical Education.*

No. F. 1-1/67-*T.2.*—In partial modification of the Government of India, the late Department of Education Resolution No. F. 16-10/44-E.3, dated 30th November, 1945, as amended from time to time (up to 14th April, 1967), the President is pleased to order that the following clause may be added after clause (t) of paragraph 3(1) of the above mentioned Resolution relating to the constitution of the Council :—

(u) *Member-Secretary.*

The President is also pleased to order that the word "Secretary" wherever it occures in paragraph 5 of the above mentioned Resolution may be read as "Member-Secretary".

ORDER

ORDERED that the Resolution may be published in the Gazette of India.

ORDERED that the copies may be circulated to all the State Governments including Union Territories and Ministries of the Government of India.

L. S. CHANDRAKANT, Jt. Educational Adviser (Technical)

MINISTRY OF TOURISM AND CIVIL AVIATION

RESOLUTION

New Delhi, the 8th January 1968

No. 20-*AC*(9)/67.—Government have, in their Resolution No. 20-AC(9)/67 dated the 8th November, 1967, appointed a Committee called the Air Corporations Job Evaluation Committee consisting of Shri S. N. Guha Roy, a retired Judge of the Calcutta High Court. The Committee was to be assisted in its work by Air Commodore M. L. Akut of the Indian Air Force and Shri Y. R. Malhotra, Director of Air Safety in the Civil Aviation Department as technical experts/assessors.

2. Government have now decided that Shri P. M. Reddy, ex-General Manager, H.A.L., Bangalore, and Wing Commander D. E. Gomes of the Indian Air Force (Technical Engineering Section) will also assist the Committee as Technical Experts/Assessors.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be published in the Gazette of India.

J. N. GOYAL, Jt. Secy.

(4) Prime Ministers' Drought Relief Fund :		
(*a*) in 12/66	85,000·00	
(*b*) in 4/67	45,000·00	
	1,30,000·00	2,00,000·00
2. Payment to U.P. Famine Orphans		180·25
3. Misc. Bank Charges ..		12·25
4. Honoraria to Accountants		275·00
5. Closing Balance .. .. Fixed Deposit for 1 year	75,000·00	
Current Account ..	4,388·31	79,388·31
		2,79,855·81

BISHAN CHAND, Honorary Secretary

MINISTRY OF TRANSPORT AND SHIPPING
(Transport Wing)

RESOLUTION

New Delhi, the 5th January 1968

(PORTS)

No. 8-*PG*(204)/67.—The Government of India have received the Administration Report of the Port of Bombay for the year 1966-67. The noteworthy features for the Report are reviewed below :—

2. *Financial Position*

The total revenue of the Port Trust during the year under review was Rs. 2,077.71 lakhs as against Rs. 2,064.33 lakhs in the previous year. The total expenditure during the year 1966-67 was Rs. 1,883.41 lakhs as against Rs. 1,692.99 lakhs in the year 1965-66. There was thus a surplus of Rs. 194.30 lakhs. The increase in expenditure was mainly under the headings General charges, Wet Docks, Lands & Bulidings and Railway Dpartment and was due to increase in staff, dearness allowance, payment of second interim relief, payment of arrears on account of revision of pay scales, *ex-gratia* payments in lieu of bonus, children's educational assistance schemes.

The total balance in the Port Trust's Reserve Funds amounted to Rs. 39.39 crores at the end of the year 1966-67. Of the outstanding debt of Rs. 14.56 crores, the amount due to the public was Rs. 5.68 crores and to Government Rs. 7.91 crores, the balance of Rs. 0.97 crores being internal loans held by the Trustees themselves. For repayment of loans, the Trustees have built up a balance of Rs. 6.25 crores in the General Sinking Fund and of Rs. 3.12 crores in a Suspense Account to repay the loan taken from Government for the Marine Oil Terminal.

3. *Traffic*

The dead weight tonnage handled at the port during 1966-67 was 18,266,000 tonnes of which Imports accounted for 13,227,000 and Exports 5,039,000. The corresponding figures of imports and exports during the previous year were 12,976,000 and 5,140,000 tonnes respectively, totalling 18,116,000 tonnes.

The total traffic handled during the year set up and all-time high record for the port.

The number of overseas passengers who used the port during 1966-67 was 1,23,761 while the number of coastal passengers was 6,33,475.

4. *Shipping*

The number of vessels, which entered the Port during the year 1966-67 was 3,062 of 22.00 million gross registered tons as against 2,958 of 21.72 million tons in 1965-66. The largest vessel, which entered the Port during the year was the s.s. "Rotterdam", with a gross tonnage of 38,621.

The number of sailing vessels which used the port during the year 1966-67 was 33,528 as against 34,329 during the year 1965-66.

During the year 1966-67, 113 vessels used the Dry Docks. The number of vessels which were berthed in the Wet Docks for repair purposes was 73 including 15 vessels berthed at the Alexandra Docks.

5. *Works*

The total expenditure on Capital Account was Rs. 453.99 lakhs. The following are some of the important works on which expenditure was incurred during the year 1966-67 :—

S. No.	*Name of work*	*Expenditure* (in lakhs)
1.	Dock Expansion Scheme	188.40
2.	Dredging of the Main Harbour channel Main Scheme Phase I & II.	22.46
3.	Preparation of the Master Plan for the development of the Port	16.86
4.	Purchase of 2 Nos. 30 ton capacity mobile cranes.	18.37
5.	Purchase of 4 Harbour tugs.	103.90
6.	Hospital Building for Port Trust staff.	13.21
7.	Ballard Pier Extension and the Passenger-*cum*-cargo Terminal Buildings, including cranes & other services.	12.79

6. *Port Trust Railway*

The volume of trunk traffic showed a decrease as compared to 1965-66 as in avident from the following table :—

	Wagons		
	Inward	Outward	Tonnes
1965-66	111,230	151,612	5,026,077
1966-67	95,443	151,534	4,834,300

The results of the working of the Bombay Port Trust Railway during 1965-66 and 1966-67, as worked out in accordance with the revised method approved by Trustees, are given below :—

	Revenue	Expenditure	Surplus (+) Deficit (—)
	(figures in lakhs of Rs.)		
1965-66	130,44	177,04	(—) 46·61
1966-67	138,33	198,67	(—) 60·34

The worsening of the financial position is due to the small increases under through freight, siding Charges, and terminals being offset by a fall under shunting, rebooking and diversion and to increase in expenditure which is primarily due to a rise in the establishment cost owing to enhancement of the rates of dearness allowances, grant of additional interim relief, *ex-gratia* payments in lieu of bonus, reimbursement of Tuition Fees and payment of children's educational allowances and increase in the cost of permanent way materials.

7. *Turn round of shipping and pace of loading/unloading of Vessels*

The highest number of vessels using the Docks during the year 1966-67 was 101 during the fortnight ended the 15th March, 1967. The average turn-round during this fortnight was 4.1 days, as against the slowest turn-round of 7 days during the fortnight ended 31st July, 1966, when 60 vessels used the Docks.

The fastest rates of unloading and loading of vessels, which worked 1,000 tonnes and over during the year 1966-67, were as follows :—

	In tonnes Fastest average rate per day of turn round	
	1965-66	1966-67
Unloading (imports)	2844	2954
Loading (Export)	3012	2614

The cargo handled under the Piece rate scheme was 127% over the datum in 1966-67.

8. *Estate Department*

The revenue of the Estate Department from all sources amounted to Rs. 216.95 lakhs (excluding Rs. 14.86 lakhs collected by the Docks Department), as against Rs. 193.90 lakhs in 1965-66.

9. *Labour*

Industrial relations in the port were fairly satisfactory during the year.

The Port Trust's Welfare measures covered a variety of activities namely, sports, recreations, variety entertainments, excursions, scholarships, canteens, general medical attention women's clinics, reading rooms, and libraries etc. A contribution of Rs. 3.79 lakhs was made from Revenue to the Employees' Welfare Fund.

10. *Staff*

The total expenditure on staff during 1966-67 amounted to Rs. 1040.05 lakhs as against Rs. 914.10 lakhs in the previous year. The increase of Rs. 125.95 lakhs was mainly due to payment of arrears to Officers as a result of revision of their pay scales, the grant of *ex-gratia* payments in lieu of bonus and a second interim relief to Class III and Class IV employees, upward revision of dearness allowance, introduction of the scheme of educational assistance, additional staff, etc.

The total expenditure on medical aid amounted to Rs. 12.34 lakhs during the 1966-67 as against Rs. 10.14 lakhs in the previous year.

11. *Acknowledgement*

The Port Trust Board carried out another year of useful work and the Government of India view it with appreciation.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

Z. S. JHALA, Jt. Secy.

MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER

RESOLUTION

New Delhi, the 6th January 1968

No. DW.V.510(3)/65.—In continuation of this Ministry's Resolutions of even number dated the 28th May, 1965, 24th August, 1965, 21st March, 1966, 16th July, 1966, 19th November, 1966, 26th May, 1967 and 17th July, 1967, Government of India is pleased to extend the period for submission of the final report by the Technical Committee constituted to devise long term measures for the protection of Chitauni bund from the ravages on the river Great Gandak, up to 29th February, 1968.

ORDER

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette to the State Governments of Uttar Pradesh and Bihar for information.

ORDERED that the Resolution be published in the Gazettee of India and that the State Governments of Uttar Pradesh and Bihar be requested to publish it in the State Gazette for general information.

P. R. AHUJA, Jt. Secy.

RESOLUTION

New Delhi, the 8th January 1968

No. 33/4/67-*DW.I.*—In this Ministry's Resolution No. F.11(2)/54-DW.I, dated the 14th April, 1955 (as amended from time to time), constituting the Chambal Control Board, the following entry may be made under paragraph 3 after entry number (i) :—

(ii) Deputy Minister, Ministry of Irrigation & Power, Government of India. *Member*

The existing entries (ii) to (xvii) may be renumbered as (iii) to (xviii).

ORDER

ORDERED that this Resolution be communicated for information to the State Governments of Madhya Pradesh and Rajasthan, the Ministry of Finance and the Planning Commission.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India and that the State Governments of Madhya Pradesh and Rajasthan be requested to publish it in the State Gazettes for general information.

K. S. S. MURTHY, Dy. Secy.

MINISTRY OF LABOUR, EMPLOYMENT AND REHABILITATION

(Department of Labour and Employment)

RESOLUTION

New Delhi, the 11th January 1968

No. WB-17(23)/67.—Decisions on the Report of the Wage ›ard for Non-Journalists employees of the newspaper in-ıstry, were announced in Government Resolution No. WB-(7)/67, dated the 18th November, 1967. A discrepancy s since been poin'ed out in regard to the grouping of ıployees of Weeklies and Periodicals in Chapter IV of the ›ard's Report, a copy of which was appended to the afore-id Resolution. It has been verified that the discrepancy is due to an inadvertant error. The following corrections in Chapter IV of the Report are notified for information of all concerned :—

Corrections

(i) In para 4.23 (Grouping of Non-Journalists) the heading of clause (a) shall be *substituted* as follows :—

"(a)—In daily newspapers class I, class II and class III and weeklies and periodicals class I."

(ii) In Group II, under Clause (a), the words "P.R.O.s (Class I & II Papers)" shall be *amended to read* as "P.R.O.s (Class I & II daily newspapers)".

(iii) In para 4.23, the heading of Clause (c) shall be *substituted* to read as under :—

"(c) Weeklies and Periodicals (other than Class I)".

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

HANS RAJ CHHABRA, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1968